नगर निगम में आप के ही बंदे तो लूट करवा रहे हैं सीएम साहब

खट्टर ने खुद माना कि बीते छह-सात साल में नगर निगम फरीदाबाद लूट भी रहा है और इसकी लुटाई भी हो रही है

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) नगर निगम में खुली लूट मची है, सार्वजनिक रूप से कुबूल करने वाले मुख्यमंत्री खट्टर इस लूट पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। वजह, इस लूट में उनके नेता और अधिकारी ही तो शामिल हैं। विकास कार्यों के नाम पर लूट कमाई का बंटवारा कराने के लिए निगम में सत्तापक्ष के चहेते ठेकेदार और अधिकारी ही तो लगाए गए। जिस अधिकारी ने निगम और सरकारी खजाने की हिफाजत करनी चाही उसे इन्हीं नेताओं के इशारे पर दूध की मक्खी की तरह निकाल कर मलाई खाने वाले को तैनात कर दिया गया। विज्ञापन विभाग का चार्ज ईमानदार निगम सचिव जयदीप से लेकर भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता ओमबीर को दिया जाना इसका हालिया उदाहरण है।

दो सितंबर को हुई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सेक्टर 62-63 के लोगों ने जलभराव की समस्या का रोना रोया तो खट्टर ने उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय नगर निगम में भ्रष्टाचार का अपना रोना शुरू कर दिया मानो कि इसके लिए वे शिकायतकर्ता ही जिम्मेदार हों। उन्होंने कहा कि बीते साठ-आठ सालों में नगर निगम में जितना भ्रष्टाचार हुआ है प्रदेश के अन्य निगमों में नहीं हुआ, यहां लूट हो रही है और लुटवाई भी हो रही है। सीएम ने सार्वजनिक मंच पर भ्रष्टाचार तो कुबूल कर लिया लेकिन जांच करा भ्रष्टों को पकड़वाने के बजाय सिर्फ ये कह कर पल्ला झाड़ लिया कि जो गलत थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं बताया कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्या वसूली हुई। निगम के भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर होने का दावा करना जुमले से ज्यादा कुछ नहीं था।

बैठक में उन्हें जानकारी दी गई कि नगर निगम में अवैध विज्ञापन का चार्ज उसी एसई ओमबीर को दे दिया गया है जिस पर पहले ही विज्ञापन घोटाले में लिप्त होने का आरोप है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इससे ही पता चलता है कि वह भ्रष्टाचार के प्रति असल में कितने गंभीर हैं और निगम को कौन लुटवा रहा है। एसई ओमबीर पर विज्ञापन घोटाले के अलावा अन्य घोटालों के भी आरोप हैं। तारीफ की बात तो यह है कि ओमबीर पर घोटालों के आरोप भी लगते रहते हैं और लगातार पदोन्नतियां भी मिलती रहती हैं।

जाहिर है कि घोटालों का आरोप लगाना और उन्हें हटाना खट्टर के राज में ये एक अच्छा खासा व्यापार बन चुका है।

निगम सचिव जयदीप ने विज्ञापन माफिया के जिन अवैध विज्ञापनों को हटवाया था, एसई ओमबीर को चार्ज मिलते ही रातों रात उन जगहों पर नए विज्ञापन लगा दिए गए। मुख्यमंत्री के आने से पहले ही ओमबीर की शह पर विज्ञापन माफिया ने फिर से शहर को रंग डाला, मुख्यमंत्री इन्हें हटवाने तक का आदेश नहीं जारी कर सके। करते भी कैसे, सरकार ने ही तो निगम में भ्रष्ट अफसरों को लूट कमाई करने की खुली छूट जो दे रखी है। निगम के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक दो सौ करोड़ रुपयों का घोटाला मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे एक अधिकारी के इशारे पर हुआ था। कैग ने भी 184 करोड़ रुपये के एक अन्य घोटाले का खुलासा किया इसमें खट्टर के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के चहेते ठेकेदार सतबीर सिंह को फायदा पहुंचाने के लिए 4 लाख की फाइलों का बजट बढ़कर 99 लाख कर दिया गया। बड़ी बात यह रही कि कई जगह बजट तो बढ़ाया गया, लेकिन काम हुआ ही नहीं।

इस साल की शुरूआत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने नगर निगम में 50 करोड़ रुपये का एक अन्य घोटाला उजागर किया था। इसमें दस वार्डों में बिना ईंट लगाए ही एक ही ठेकेदार की तीन फर्मों को 32 करोड़ का भुगतान किया गया था। यह ठेकेदार भाजपा से जुड़ा है। 2018 में आरटीआई कार्यकर्ता वरुण श्योकंद ने विज्ञापन विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया था। तब भी निगम अधिकारी अवैध विज्ञापन माफिया की मिलीभगत से प्रति माह करोड़ों रुपये डकार रहे थे, ये खेल आज तक जारी है।

नगर निगम डिवीजन तीन में अधीक्षण अभियंता ओमबीर ने अक्तूबर 2019 में विज्ञापन एजेंसी श्याम इंटर प्राइजेज से यूनीपोल, गैंट्री लगाने का अनुबंध किया। नियमों के खिलाफ जाते हुए चालाकी से यह अनुबंध नगर निगम के बजाय अधीक्षण अभियंता के नाम कराया गया। यदि यह अनुबंध नगर निगम से होता तो उसके उपबंधों में आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता था, ऐसा करने से ओमबीर के हाथों में यह अधिकार चला गया। अनुबंध के अतिरिक्त ओमबीर ने अवैध विज्ञापन माफिया को यूनीपोल, गैंट्री और बैनर-पोस्टर, होर्डिंग लगाने की खुली छूट दे दी। यह अवैध विज्ञापन माफिया सांसद-मंत्री-विधायक के करीबी हैं। इसी कारण उन्हें मोटी कमाई वाले विभाग में जगह दी गई। नतीजा करोड़ों रुपये के विज्ञापन घोटाले के रूप में सामने आया।

जीरो टॉलरेंस का जुमला फेकने वाले मुख्यमंत्री नगर निगम में भ्रष्टाचार पर चिंता तो जता रहे हैं लेकिन दागी चाल-चरित्र वाले अधिकारियों को हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, कर भी कैसे पाएंगे, इन अधिकारियों को उनकी सरकार ने ही तो अपनी पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर ये पद सौंपे हैं। यदि भ्रष्टाचार समाप्त करने की सच्ची नीयत है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के नेता और जन प्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए फिर निगम में इनकी चाटुकारिता करने वाले अधिकारियों पर, लेकिन इसके लिए जुमला नहीं दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है।

नगर निगम हो या 'हूडा' इनमें तैनात होने वाले अफसरों को ऐसे लगाया जाता है मानो कि वे नीलामी में यहां की पोस्टिंग खरीद कर लाए हों। बीते आठ-नौ साल का इतिहास देखने से पता लगता है कि कोई भी अधिकारी साल छह महीने से अधिक इन पदों पर तैनात नहीं रह पाता, क्योंकि बोली देने वाले अन्य अधिकारी ऊंची बोली लगाकर मैदान में आ जाते हैं। इसी लूट कमाई के बदौलत सेक्टर 15 में भाजपा का चार मंजिला भव्य कार्यालय बन पाया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर व अन्य नेताओं की जायदादों में जो दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है वह भी इसी लूट कमाई के चलते हो रही है।

लूट कमाई में बाधक जयदीप जैसे अफसर नहीं चाहिए

2004 बैच के एचसीएस अधिकारी जयदीप ने बतौर निगम सचिव अवैध विज्ञापन माफिया पर अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी का वार किया, विज्ञापन माफिया की कमर तोड़ते वक्त उन्होंने मंत्री किशनपाल गूजर को भी नहीं बख्शा तो खट्टर सरकार की 'ईमानदारी' न जाने कहां काफूर हो गई। चंद घंटों बाद ही उनसे विज्ञापन संबंधित अधिकार वापस ले लिए गए। इस मामले से जहां खट्टर सरकार एवं स्थानीय नेताओं की पोल चौड़े में खुल गई है वहीं जयदीप ने यह साबित कर दिया है कि रीढ़ की हड्डी वाले अफसर अभी मौजूद हैं, सभी अफसर नेताओं के तलवे चाट कर उनके पैरों में रेंगने वाले नहीं होते। इस मामले ने यह भी साफ कर दिया है कि इन तमाम राजनेताओं को बिना रीढ़ की हड्डी वाले चाटुकार एवं रेंगने वाले वे अफसर ही पसंद आते हैं जो खुद भी लूटें और इन्हें भी लूट का माल खिलाएं।

एफएसएसएआई : नाम बड़े दर्शन छोटे, 2015 से जुलाई 2023 तक प्राधिकरण ने तमाम जिलों में प्रतिमाह औसतन 11 सैंपल भरे

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारी भरकम नाम पढ़ कर जनता को यह मुगालता नहीं पालना चाहिए कि वह जो भी खाद्य सामग्री खरीद रही है वह शुद्ध है क्योंकि एफएसएसएआई की उस पर कड़ी नजर रहती है। तो जान लीजिए कि इसके अधिकारी आपके बड़े शहर की सैकड़ों मिठाई, दूध, बेकरी, चाय-पकौड़े की दुकानों, ढाबे, होटल, एक्सपेलर, चक्की, मसाला चक्की आदि खाद्य सामग्री बनाने वाली संस्थाओं में से प्रत्येक महीने औसतन केवल 11 सैंपल ही भरते हैं। यह आंकड़ा 2015 से 31 जुलाई 2023 तक पूरे प्रदेश का है।

एफएसएसएआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्राधिकरण ने अप्रैल 2015 से 31 जुलाई 2023 तक प्रदेश में 24 हजार खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भरे। यानी पूरे प्रदेश में प्रति माह 242.42 सैंपल लिए गए। जिलों के आधार पर यह औसत महज 11 सैंपल प्रति जिला प्रति माह होता है। किसी भी शहर में खाद्य सामग्री उत्पादक, विनिर्माता, विक्रेता सैकड़ों की संख्या में रहते हैं। केवल दूधियों और दूध डेयरियों की संख्या ही सौ से अधिक होती है। ऐसे में पूरे महीने में महज 11 सैंपल लिया जाना प्राधिकरण की अकर्मण्यता प्रदर्शित करती है।

प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लंबे समय से खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) के 45 में से 43 पद खाली चल रहे हैं। अब प्राधिकरण इन खाली पदों में से केवल 9 पदों पर पशु चिकित्सकों को भर्ती किया है। सवाल यह है कि जब इन पदों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों से ही भरना था तो बाकी को खाली क्यों छोड़ा गया। मोटी कमाई वाले इस पद पर तो आने के लिए बहुत से लोग तैयार होंगे। मोटी कमाई वाला पद पाने के लिए मोटा सुविधा शुल्क भी चुकाना पड़ता है। बाकी पद भरने के लिए सुविधा शुल्क चुकाने वालों को तलाशा जा रहा होगा, इसीलिए देर हो रही है।

वैसे भी इन अधिकारियों का काम ही क्या है। मौके पर सैंपल तो लैब असिस्टेंट ही भरता है, एफएसओ का काम भरे गए सैंपल पर हस्ताक्षर कर सत्यापित करने भर का ही है। सैंपल की जांच तो लैब में ही होती है। जांच रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की जाती है, इसके लिए एफएसएसएआई की कानूनी शाखा है। एफएसओ तो सैंपल भरने का डर दिखा कर ही हजारों रुपये कमा सकते हैं जैसा कि पृथ्वी सिंह ने 2015 में सेक्टर 12 स्थित हल्दीराम की दुकान से गुलाबजामुन भरने के नाम पर पचास हजार रुपये वसूले थे।

फरीदाबाद, पलवल सहित तीन जिलों का काम देख रहे एफएसओ सचिन शर्मा की कार्यशैली किसी से छिपी नहीं है। नकली खाद्य सामग्री की शिकायत करने पर वह शिकायतकर्ता से ही सैंपल भर कर लाने को कहते हैं। उनके अनुसार यदि शिकायतकर्ता का दिया हुआ नमूना फेल होगा तब उसके बाद वह दुकानदार के पास जाकर नमूना भरेंगे। यही हाल जिला अभिहित अधिकारी पृथ्वी सिंह का है, वह भी स्टाफ की कमी का रोना रोकर कुछ नहीं करते। दरअसल इन अधिकारियों को सैंपल नहीं भरने के मोटे पैसे मिलते हैं, इसलिए ये काम करना ही नहीं चाहते।

देश में पर्व का सीजन शुरू हो चुका है, हाल ही में रक्षाबंधन बीता और जन्माष्टमी है, आगे नवरात्रि, दशहरा, दीपावली आने वाले है। इन त्योहारों पर मिठाई आदि की अनेक अस्थायी दुकानें खुलती हैं। वर्तमान में एनआईटी दशहरा ग्राउंड में बड़ा मेला लगा है।

मेले में दर्जनों खाद्य सामग्री की दुकानें लगाई गई हैं लेकिन जिस तरह प्राधिकरण के अधिकारियों ने रक्षाबंधन और 15 अगस्त के करीब दुकानों का निरीक्षण कर सैंपल भरने की जहमत नहीं उठाई उसी तरह मेले में भी सैंपल नहीं भरे गए। यहां आने वाले ग्राहकों को दुकानदार चाहे जैसे घटिया तेल में तल कर, या बासी सामग्री खिलाकर बीमार करें, एफएसएसएआई को कोई असर नहीं पड़ेगा।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421